भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2638
बुधवार, 11 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विशाखापट्टनम और नेल्लोर जिलों में तटीय कटाव

†2638. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विशाखापट्टनम और नेल्लोर जिलों में समाजिक रूप से वंचित आबादी वाले क्षेत्रों के तटीय कटाव पर कोई अध्ययन किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार द्वारा इन समुदायों की सुरक्षा के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) जी हाँ।

(ख) राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय, ने समुद्री कटाव का आकलन किया है और 1990 से समुद्री कटाव वाले भारत के तटीय क्षेत्रों की पहचान की है। जुलाई 2018 में "भारतीय तट के साथ तटरेखा परिवर्तनों का राष्ट्रीय आकलन" पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी और तटरेखा संरक्षण उपायों को लागू करने के लिए रिपोर्ट को विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों और हितधारकों के साथ साझा किया गया था। एटलस का एक अद्यतन संस्करण, साथ ही रिपोर्ट का एक डिजिटल संस्करण, जिसमें सभी मानचित्र शामिल हैं, 25 मार्च 2022 को जारी किया गया था। विशाखापत्तनम और नेल्लोर जिलों के लिए तटरेखा परिवर्तन विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं।

जिले का नाम	**तटीय लंबाई (किमी में)**	**कटाव (% में)**	**स्थिर (% में)**	**संवृद्धि (%में)**
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	**111.2**	**35.1**	**36.2**	**28.7**
विशाखापट्टनम	**68.08**	**26.9**	**49.5**	**23.7**
सम्पूर्ण	**179.28**	**31**	**42.85**	**26.2**

नेल्लोर और विशाखापत्तनम जिलों के कटाव की संभावना वाले भाग नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

क्र. सं.	तटीय क्षेत्र	जिला	वर्गीकरण
1	कृष्णापट्टिनम बंदरगाह के उत्तर में	नेल्लोर	कम कटाव
2	SDSTPS से कोडुरु तट तक		कम कटाव
3	गंगापटनम इनलेट		कम कटाव
4	पेन्ना रिवर एशचुअरी		अधिक कटाव

5	रामतीर्थम समुद्र तट		कम कटाव
6	ईसकापल्ले तट		कम कटाव
7	जुवालाडिनने तट		कम कटाव
8	कोथाबंगरुपलेम मछली पकड़ने के बंदरगाह से थुम्मालपेंटा समुद्र तट तक		कम कटाव
9	रामायापट्टनम तट		कम कटाव
10	करेडु तट		कम कटाव
11	यारदा	विशाखापट्टनम	कम कटाव
12	आरके तट		कम कटाव
13	मंगामारी पेटा से भीमिली तक		कम कटाव
14	भीमुनिपट्टनम से पेदानागमय्यपालेम तक		कम कटाव

(ग) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने तटीय कटाव से निपटने और तटीय अवसंरचना विकास गतिविधियों का समर्थन करने में आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता के लिए राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से तटरेखा प्रबंधन योजना तैयार की है। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा एनडीएमए को प्रस्तुत किए जाने हेतु डीपीआर तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है, जो इस प्रकार है:

- SDSC-SHAR, श्रीहरिकोटा - तटीय कटाव को कम करने और SHAR की कार्यनीतिक अवसंरचना की सुरक्षा के लिए;
- ओएनजीसी, वोडालारेवु - कटाव को कम करने और ओएनजीसी की कार्यनीतिक तटवर्ती सुविधाओं की सुरक्षा के लिए
- उप्पाडा, काकीनाडा - कटाव वाले मछली पकड़ने वाले गांवों और कोरिंगा मैंग्रोव वनों जैसे पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों पर विचार करते हुए काकीनाडा तट के लिए एक एकीकृत तटीय सुरक्षा रणनीति का प्रस्ताव रखा।
- विशाखापट्टनम - विशाखापट्टनम बंदरगाह से भीमुनिपट्टनम क्षेत्र के लिए एक एकीकृत तटीय सुरक्षा कार्यनीति तैयार की गई और विशाखापट्टनम महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (वीएमआरडीए) के सहयोग से डीपीआर एनडीएमए को प्रस्तुत की गई।
- श्रीकाकुलम - नागवल्ली और वम्सधारा नदियों के संगम बिंदुओं पर समस्याओं के समाधान और स्थानीय मछुआरा समुदाय को समर्थन देने के लिए डीपीआर।

तकनीकी समाधानों और कार्यनीतियों का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है और राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार को सभी तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन, अनुकूलन और शमन उपायों की योजना के लिए देश के पूरे तट के लिए जोखिम रेखा को चित्रित किया है। जोखिम रेखा जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि सहित तटरेखा परिवर्तनों का संकेत है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सीआरजेड अधिसूचना, 2019 में समुद्री कटाव के कारण भारतीय तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान हैं।

इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई सिफारिशों के आधार पर, तटीय और नदी कटाव के कारण लोगों के प्रभावी विस्थापन के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (NDMF) के तहत तटीय और नदी कटाव के लिए निधियों के अनुमोदन और इन्हें जारी करने के लिए दिशा-निर्देश और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) के तहत कटाव से प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर नीति को गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर जारी कर दिया गया है।

*****